एस. मोहम्मद इस्पहानी

बनाम

योगेन्द्र चांडक एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1720/2017)

अक्टूबर 04, 2017

[एक। के. सीकरी और अशोक बि-इयुशान, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 319- आरोप पत्र में नामित नहीं किए गए व्यक्तियों को उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने की अदालत की शक्ति- जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस जांच के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे फंसाए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो अदालत शक्तिहीन नहीं होती है, और सम्मन के चरण में, यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में उसका नाम न हो, तो वह ऐसा कर सकती है- उस स्तर पर, शिकायतकर्ता को भी एक विरोध याचिका दायर करने का मौका दिया जाता है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों को भी बुलाने का आग्रह किया जाता है, जिनका आरोप पत्र में नाम नहीं था- एक बार वह चरण बीत जाने के बाद, धारा 319 के आधार पर न्यायालय अभी भी शक्तिहीन नहीं है- हालाँकि, यह धारा तब शुरू हो जाती है जब मुकदमे के दौरान प्रस्तावित अभियुक्तों के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।

धारा 319- का आह्वान- वास्तव में शिकायतकर्ता अपीलकर्ताओं-जमींदारों के परिसर में किरायेदार था, जिसके खिलाफ बेदखली डिक्री अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त की

गई थी- जिस दिन निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कब्जा दिया जाना था, वास्तव में शिकायतकर्ता ने एक शिकायत प्रस्तुत की कि घातक हथियारों से लैस 50-60 उपद्रवी तत्वों ने उसके किराए के परिसर में प्रवेश किया और उसके कर्मचारियों को धमकाया और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और कीमती सामान भी ले गए- धारा 379, 427, 341 आर/डब्ल्यू धारा 34 पीसी के तहत और तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (आई) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं का नाम नहीं था- वास्तविक शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद, उसके बेटे पीडब्लू-1 ने अपने बयान में अपीलकर्ताओं और जमानतदार का भी नाम लिया- धारा 319 के तहत दायर आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया- पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ताओं को भी आरोपी के रूप में फंसाने का निर्देश दिया- अपील पर, माना गया: उपलब्ध साक्ष्य अपीलकर्ताओं को मामले में आरोपी के रूप में फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं थे- पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें अपीलकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया था, हालांकि, शिकायतकर्ता ने उस स्तर पर कोई विरोध याचिका दायर नहीं की थी- कथित घटना के समय अपीलकर्ता/मकान मालिक कथित तौर पर साइट पर मौजूद नहीं थे। सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में कोई 'सबूत' नहीं है जिसके आधार पर उन्हें बुलाया जा सके क्योंकि [आरोपित व्यक्तियों- पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 ने घटनास्थल पर हुई घटना के बारे में गवाही दी थी और जिस तरीके से उपस्थित व्यक्तियों ने कथित तौर पर व्यवहार किया- जहां तक अपीलकर्ता-बेलीफ का संबंध है, एफआईआर में या अदालत में पीडब्लू 1 से 6 के बयानों में कोई विशेष आरोप नहीं था- एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान पुलिस को अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और यहां तक कि विभाग को भी विभागीय जांच में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला- इसके अलावा, परीक्षण के दौरान, अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ कोई 'मजबूत और ठोस सबूत' सामने नहीं आया जिसके

आधार पर उसे बुलाया जा सके- दंड संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ताओं को बुलाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया- तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992- धारा 3- दंड संहिता, 1860- धारा 379, 427, 341 आरएलडब्ल्यू धारा 34।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

1. सीआरपीसी की धारा 319 उन लोगों को भी इसमें फंसाने के लिए है, जिन्हें आरोप पत्र दाखिल होने के समय फंसाया नहीं गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत को पता चला कि उन्हें बुलाने और मुकदमे का सामना करने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर आ गए हैं। . मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश से पता चलता है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज करते समय, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दो विचारों से प्रभावित थे: शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपीलकर्ताओं, यानी मकान मालिकों और जमानतदार के बीच हुई कथित साजिश के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। इसके अलावा अन्य गवाहों, यानी पीडब्ल्यू 2, 3 और 4, जो वास्तव में शिकायतकर्ता की कंपनी में काम कर रहे थे, ने अपीलकर्ताओं के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। शिकायतकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, उपलब्ध 'साक्ष्य' अपीलकर्ताओं/प्रस्तावित आरोपियों को मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था; पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें अपीलकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने उस स्तर पर कभी कोई विरोध याचिका दायर नहीं की। उच्च न्यायालय ने विषय वस्तु को ठीक से नहीं निपटाया और अपीलकर्ता के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूतों के अभाव में भी, उसने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को आरोपी

व्यक्तियों के रूप में बुलाने में अपने विवेक का प्रयोग किया। [पैरा 27,30,33] [42-जी; 46--एफ-एच; 47-ए, ई]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92: [2014] 2 एससीआर 1; बिजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2017) 7 एससीसी 706- पर निर्भर

2. जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस जांच के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे फंसाए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है, और समन के चरण में, यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाया जाना चाहिए, भले ही आरोप पत्र में उसका नाम न हो, वह ऐसा कर सकती है। उस स्तर पर, शिकायतकर्ता को भी एक विरोध याचिका दायर करने का मौका दिया जाता है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों को भी बुलाने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम एफआईआर में था लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक बार वह चरण बीत जाने के बाद भी न्यायालय सीआरपीसी की धारा 319 के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब लागू होती है जब मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं। इसे देखते हुए, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में भरोसा करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था। यह केवल पुष्टिकारक सामग्री हो सकती है। पहले उदाहरण में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 'साक्ष्य' पर विचार किया जाना था। जहां तक अदालत में दिए गए पीडब्लू-1 के बयान का सवाल है, उक्त बयान को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपीलकर्ताओं/जमींदारों की ओर से किसी साजिश का आरोप नहीं लगाया है। दरअसल, किसी भी गवाह ने ऐसा नहीं कहा है. इसके अभाव में, इस महत्वपूर्ण तथ्य के साथ कि कथित घटना होने पर ये अपीलकर्ता/मकान मालिक

कथित तौर पर साइट पर मौजूद नहीं थे, सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में कोई 'सबूत' नहीं है जिसके आधार पर वे आरोपी व्यक्ति के रूप में तलब किया जा सकता है। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 ने घटनास्थल पर हुई घटना और जिस तरीके से लोगों ने हमला किया, उसके बारे में गवाही दी है। कथित तौर पर मौजूद हैं व्यवहार. पीडब्लू-4 के बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि "बाद में मुझे पता चला कि उक्त लोग पुलिस अधिकारी नहीं हैं, लोगों को इमारत के मकान मालिकों ने भेजा था। वह बयान आईपीसी के उन प्रावधानों के तहत आरोप का सामना करने के लिए अपीलकर्ताओं/मकान मालिकों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है जिनके तहत अन्य पर आरोप लगाए गए हैं। [पैरा 34,35] [48-बी-जी]

3. जहां तक अपीलकर्ता/जमानतदार का सवाल है, एफआईआर या अदालत में पीडब्लू 1 से 6 के बयान में कोई विशेष आरोप नहीं है। जहां तक जमानतदार के खिलाफ हुई विभागीय जांच का सवाल है तो उसे केवल कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया है, अन्य आरोप का नहीं। उक्त पूछताछ में, हालांकि वास्तविक शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और उसने एक अन्य गवाह भी पेश किया, इन आरोपों पर अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके कारण जांच अधिकारी ने भी माना कि ऐसा कोई आरोप साबित नहीं हुआ है. इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक निर्धारक कारक नहीं है क्योंकि आपराधिक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, प्रकृति में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालाँकि, प्रासंगिक बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान पुलिस को अपीलकर्ता/बेलिफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और यहां तक कि विभाग को भी विभागीय जांच में उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। इसके अलावा, मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ कोई 'मजबूत और ठोस सबूत' सामने नहीं आया जिसके आधार पर उसे बुलाया जा सके। [पैरा 36] [48-एच; 49-ए-सी]

इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (1989) 2 एससीसी 132: [1989] 1 एससीआर 718- अनुपयुक्त ठहराया गया

गीता राम बनाम वेदी राम और अन्य (2002) 10 एससीसी 499; सुमन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2010) 1 एससीसी 250- संदर्भित

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2014] 2 एससीआर 1	निर्भर	पैरा 15
(2017) 1 धारा 106	निर्भर	पैरा 15
[1989] 1 एससीआर 718	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 24
(2002) 10 धारा 499	संदर्भित	पैरा 24
(2010) 1 धारा 250	संदर्भित	पैरा 25

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1720/2017

आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 628/2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.06.2017 से

साथ

सी.आर.एल. ए.नंबर 1721 एवं 1722/2017

सिद्धार्थ लूथरा, संजय आर. हेगड़े, राकेश खन्ना, वरिष्ठ वकील, एन. आनंद वेंकटेश, एस. नितिन, सुश्री सोनाली करवासरा, सुश्री अरुणिमा सिंह, पी. किशोर, करुणाकर महालिक, नितिन ठुकराल, आर. चंद्रचूड़, श्रीराम पी, सलाहकार. अपीलकर्ता के लिए.

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ वकील, अमरजीत सिंह बेदी, वरुण चंडियोक, योगेश कन्ना, सुश्री महालक्ष्मी, सुजाता बगाची, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का फैसला **न्यायाधीश ए.के. सीकरी** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रतिवादी नंबर 1 के पिता गिरधारीलाल चांडक (बाद में "वास्तविक शिकायतकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने इन अपीलों में चार अपीलकर्ताओं सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 27 अप्रैल, 2007 को पुलिस निरीक्षक, सीबीसीआईडी-मेट्रो विंग, एग्मोर, चेन्नई के साथ। आरोप है कि दोपहर करीब 12.30 बजे घातक हथियारों से लैस 50-60 उपद्रवी तत्व शिकायतकर्ता के परिसर में घुस आए और उनके कर्मचारियों को धमकाया। उन्होंने सभी कीमती सामान जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य प्राचीन मूल्यवान वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन वस्तुओं को सड़क पर फेंक दिया और 'लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य प्राचीन मूल्यवान वस्तुओं को ले गए, जो परिसर में पड़े थे, जिसे दरवाजा नंबर 35, नया दरवाजा नंबर 9, अन्ना सलाई, चेन्नारी -2 के नाम से जाना जाता है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलकर्ता, मेहदी इस्पहानी, अली इस्पहानी और एस. मोहम्मद इस्पहानी उपरोक्त परिसर के मकान मालिक हैं, जहां वास्तविक शिकायतकर्ता किरायेदार था। मकान मालिकों ने वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें 26 फरवरी, 2007 को बेदखली के आदेश पारित किए गए थे और बेदखली के आदेश के खिलाफ वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा अपील की गई थी, जो VII, लघु वाद न्यायालय, चेन्नई के समक्ष लंबित थी। 'हालांकि, अपीलीय अदालत द्वारा बेदखली आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी और अंतरिम रोक देने से इनकार इस अदालत तक बरकरार रखा गया था। अपीलकर्ताओं/जमींदारों के अनुसार, उन्होंने निष्पादन न्यायालय 11वें से कब्जे का वारंट प्राप्त किया था, न्यायालय के जमानतदार,

अर्थात्, आई. जयारमन, जो चौथे अपीलकर्ता हैं, 24 जुलाई, 2007 को डिक्री को क्रियान्वित करने और कब्जा लेने के लिए किरायेदार परिसर में गए थे।

3. पुलिस ने शुरू में वास्तविक शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक ओपी 29386/2007 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2007 द्वारा सीबीसीआईडी को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, पुलिस द्वारा अपराध कांड संख्या 3/2008 दर्ज किया गया था, अंततः, आईपीसी की धारा 341 के साथ पठित धारा 379, 427, 341 और तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 3(1) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। इस आरोपपत्र में अपीलकर्ताओं का नाम नहीं था. मुकदमे के दौरान, वास्तव में शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई। उनका बेटा पीडब्लू-। के रूप में उपस्थित हुआ और अपने बयान में, उसने अपीलकर्ताओं, यानी सभी तीन मकान मालिकों और बेलीफ़ का भी नाम लिया। इसके बाद, इन अपीलकर्ताओं को भी आरोपी व्यक्तियों के रूप में बुलाने के लिए विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया गया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 17 अगस्त, 2015 के आदेशों के तहत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। बर्खास्तगी के उस आदेश के खिलाफ, वास्तविक शिकायतकर्ता के बेटे (इसके बाद "शिकायतकर्ता" के रूप में संदर्भित) ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। 29 नवंबर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दे दी है, जिससे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उन्हें अपीलकर्ताओं को उनके समक्ष लंबित मामले में आरोपी के रूप में फंसाने का निर्देश दिया है। यही वह व्यवस्था है जो हमारे सामने चुनौती बनी हुई है।

4. मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए, हम आवश्यक विवरण के साथ घटनाओं का कालानुक्रमिक उल्लेख कर सकते हैं।

5. वास्तविक शिकायतकर्ता- गिरधारीलाल चांडक अपीलकर्ता और उसके परिवार के परिसर में किरायेदार था। वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही (आरसीओपी नंबर 311/2006) पर, लघु वाद न्यायालय, चेन्नई ने 26 फरवरी, 2007 के आदेश के तहत उसे बेदखल करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता और अन्य मालिकों द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका पर, लघु वाद न्यायालय, चेन्नई ने 27 अप्रैल, 2007 के आदेश के तहत एक जमानतदार नियुक्त किया और किरायेदारी परिसर का कब्जा देने का निर्देश दिया। बेलिफ़ ने 27 अप्रैल, 2007 को परिसर का दौरा किया और वास्तविक शिकायतकर्ता को बेदखल करने के बाद मकान मालिकों को परिसर पर कब्ज़ा कर लिया।

6. बेदखली के आदेश के विरुद्ध वास्तविक शिकायतकर्ता ने अपील दायर की। यह रिकॉर्ड की बात है कि किरायेदार/वास्तविक शिकायतकर्ता ने निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया था जिसे लघु वाद न्यायालय, चेन्नई ने खारिज कर दिया था। स्टे न दिए जाने के खिलाफ, उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 25 अक्टूबर, 2007 को खारिज कर दिया गया। किरायेदार/वास्तविक शिकायतकर्ता ने 25 अक्टूबर, 2007 के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, लेकिन स्थगन आदेश प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि उसकी विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा 07 अप्रैल, 2008 को खारिज कर दी गई थी।

7. जिस दिन निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के आदेशों के अनुसार कब्ज़ा दिया गया, वास्तविक शिकायतकर्ता ने पुलिस को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि के.आर.अशोक के साथ

50-60 उपद्रवी तत्व थे। (अपीलकर्ताओं/मकान मालिकों का एक कर्मचारी) और सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति जो खुद को पुलिस अधिकारी होने का दावा कर रहा था, घातक हथियारों से लैस होकर किराएदार परिसर में दाखिल हुए। उन्होंने कर्मचारियों को धमकाया और मूल्यवान वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर दिया और लैपटॉप, कंप्यूटर और प्राचीन मूल्यवान वस्तुएं छीन लीं। यह भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और निष्पादन याचिका दायर किए बिना ही उन्हें और उनके उप-किरायेदारों को बेदखल करने का प्रयास किया।

8. पुलिस ने वास्तविक शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि उसी कथित घटना के संबंध में एक उप-किरायेदार की शिकायत पर मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका था और जांच की जा रही थी, जिसमें वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता को गवाह के रूप में शामिल किया गया था। इस संबंध में, 16 मई, 2007 को अभियोजन उप निदेशक, चेन्नई सिटी द्वारा एक राय भी दी गई थी जिसमें यह राय दी गई थी कि वास्तविक शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामले की जांच पहले ही की जा चुकी है और यह पाया गया कि वास्तव में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अतिरंजित हैं। इसके बाद, 25 जुलाई, 2007 को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक के आदेश पर मामला आगे की जांच के लिए अपराध शाखा सीआईडी, मेट्रो को सौंप दिया गया। हालाँकि, बाद में जब उक्त एफआईआर को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, तो शिकायतकर्ता ने वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष Crl.O.P.No.29386/2007 दायर किया, अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की। उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2007 को पुलिस को जांच करने और सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। तदनुसार, 30 जुलाई, 2008 को, पुलिस निरीक्षक, सीबी सीआईडी, मेट्रो विंग ने जांच करने के बाद 28 अप्रैल, 2007 की लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर (नंबर

3/2008) दर्ज की। आईपीसी की धारा 379 के तहत अपराध के लिए उक्त एफआईआर में तीन अपीलकर्ताओं और एक, के.आर.अशोक को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

9. सीबीसीआईडी, मेट्रो विंग, चेन्नई ने गवाहों की जांच करने और एफआईआर संख्या 3/2008 में जांच पूरी होने पर द्वितीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 15 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उक्त आरोप पत्र में अपीलकर्ताओं के नाम शामिल नहीं थे। हालाँकि, के.आर.अशोक, जो जमींदारों के प्रबंधक हैं, को अभियुक्त नंबर I के रूप में नामित किया गया था और वह मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मामला फिर XI मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई और फिर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे C.C.No.4108/2013 के रूप में फ़ाइल में लिया गया। 19 सितंबर, 2013 को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई ने उक्त 15 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 427, 341, 379 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए और सी.सी. में तमिलनाडु संपत्ति निवारण क्षति और हानि अधिनियम, 1992 की धारा 3(1) क्रमांक 4108/2013.

10. चूँकि वास्तविक शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई, उसके बेटे-प्रतिवादी नंबर 1 (शिकायतकर्ता) से पीडब्लूएल के रूप में पूछताछ की गई और 5 अन्य गवाहों से पूछताछ और जिरह की गई। पीडब्ल्यूआई की गवाही 24 अप्रैल 2014 को पूरी हुई और पीडब्ल्यू-6 की गवाही 30 सितंबर 2014 को पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की गवाही बंद होने के बाद, शिकायत ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया। (Crl. MP No. 420/2015) लोक अभियोजक के माध्यम से मकान मालिकों और जमानतदार को मामले में आरोपी व्यक्तियों के रूप में फंसाने के लिए।

11. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई ने 17 अगस्त 2015 के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। मुख्य

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी जब एफआईआर में नामित मकान मालिकों के नाम हटा दिए गए थे। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, अन्य बातों के अलावा, निम्नानुसार रिकॉर्डिंग:

> "जैसा कि इस मामले में पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, अब तक याचिकाकर्ता/अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। पीडब्लू2, ट्र. शाहुल हमीद, घटना के समय, पीडब्लूएल की कंपनी वर्ल्ड वाइड इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। ., आंशिक समय में, PW3 Tmt. चंद्रा, उक्त PWl की कंपनी में कार्यालय सहायक के रूप में काम करते थे, PW4 Tr. अक्षय कुमार, PW'l कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, PW5 श्री आनंद, PWl और PW6 श्री के रिश्तेदार थे मुथुरामलिंगम, एक टिफिन की दुकान चलाते थे, उन्होंने उत्तरदाताओं 2 से 5 के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। इसके अलावा, इस मामले में, वास्तविक शिकायतकर्ता के बेटे श्री योगेन्द्र चांडक ने पीडब्लूएल के रूप में जांच की, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में भी, प्रतिवादी 2 से 5 द्वारा की गई कथित साजिश के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में आरोप लगाया गया है। कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन, इस मामले में प्रतिवादियों 2 से 5/प्रस्तावित आरोपियों को आरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

12. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई द्वारा पारित 17 अगस्त 2015 के आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण

मामला संख्या 628/2016 के समक्ष सीआरपीसी की धारा 401 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 397 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

13. जैसा कि कहा गया है, उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित आदेशों द्वारा, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी है, जिससे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ताओं को बुलाने और उक्त मामले में मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया है। जिन कारणों ने उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की अनुमति देने के लिए राजी किया, उन्हें निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है:

> "10. पी.डब्ल्यू. 1 के साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलेगा कि शिकायत उत्तरदाताओं 1 से 4 के खिलाफ दर्ज की गई है और पहली सूचना रिपोर्ट भी उत्तरदाताओं 1 से 4 के खिलाफ दर्ज की गई है। हालाँकि, जांच के बाद, उत्तरदाताओं 1 से 4 तक के नामों को आरोप पत्र में जगह नहीं मिली। आरोप तय होने के बाद और सुनवाई के दौरान ही अभियोजन पक्ष ने इस मामले में उत्तरदाताओं 1 से 4 तक को आरोपी के रूप में फंसाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत याचिका दायर की है। P.W.1 के साक्ष्यों का अवलोकन, जो यहां याचिकाकर्ता है, ने स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं 1 से 4 द्वारा किए गए अपराध के बारे में बात की है और उदाहरण पी1 स्पष्ट रूप से याचिका में उल्लिखित अपराध के कमीशन में उत्तरदाताओं 1 से 4 की भागीदारी को भी दिखाएगा।
>
> 14. मामले के उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने सभी पहलुओं पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर आवेदन को यंत्रवत् खारिज कर दिया है। और इसलिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चेन्नई की फाइल पर Crl.M.P.No.4420/2015 में C.C.No.4108/2013 में दिए गए आदेश दिनांक 17.08.2015 को रद्द किया जाने योग्य है।"

14. उपरोक्त कथन की मुख्य विशेषताओं और मामले की कार्यवाही के तरीके पर चर्चा करते हुए, तीन अपीलकर्ताओं/जमींदारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया कि इन अपीलकर्ताओं ने परिसर के जमींदारों के रूप में वास्तविक शिकायतकर्ता के खिलाफ बेदखली का डिक्री प्राप्त किया था और कानूनी तरीकों को अपनाकर उक्त डिक्री को निष्पादित करने के लिए कदम उठाए थे। इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने निष्पादन याचिका दायर की थी जिसमें निष्पादन न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कब्जे का वारंट दिया गया था और कब्जे के वारंट को निष्पादित करने के लिए संबंधित परिसर का दौरा करने के लिए बेलीफ को नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि वास्तविक शिकायत ने बेदखली के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन वह निष्पादन पर रोक लगाने में असफल रहे क्योंकि इस अदालत तक उनके प्रयास विफल रहे थे। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, अपीलकर्ताओं/मकान मालिकों द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से कानूनी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार थे। 24 जुलाई 2007 की घटना को स्वीकार किए बिना, जैसा कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था, श्री लूथरा ने आगे कहा कि वास्तविक शिकायतकर्ता या शिकायतकर्ता भी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और उच्च न्यायालय से दूर थे। जो तथ्य उनके द्वारा एफआईआर संख्या 3/2008 में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, यह भी स्वीकृत स्थिति थी कि तीनों अपीलकर्ता/मकान मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, पुलिस द्वारा एक व्यापक जांच की गई जिसमें अपीलकर्ताओं की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई और इसलिए, उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि जब अपीलकर्ताओं को फंसाए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था, तो वास्तविक शिकायतकर्ता या शिकायतकर्ता द्वारा कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई थी, जो आरोप पत्र की सामग्री से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इन परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को

खारिज कर दिया। जो अपीलकर्ताओं को फंसाने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से देर से किया गया प्रयास था, क्योंकि वह आवेदन शिकायतकर्ता की पीडब्लू-1 के रूप में जांच करने के बहुत बाद दायर किया गया था, और उस समय तक अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य भी बंद कर दिया था।

15. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के औचित्य पर सवाल उठाते हुए, यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय केवल इस तथ्य से प्रभावित हुआ है कि अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में किया गया था और शिकायतकर्ता ने अपने बयान में जैसा कि पीडब्लू-1 ने फिर से इन अपीलकर्ताओं के नाम दोहराए और आरोप लगाया कि यह उनके कहने पर था कि वास्तविक शिकायतकर्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और चोरी कर लिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन तथ्यों पर, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अपीलकर्ताओं को बुलाने का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया है कि आरोप के चरण में और जांच के लिए परीक्षण सामग्री को नहीं बल्कि केवल साक्ष्य को देखा जाना चाहिए। परीक्षण के दौरान जो सामने आया उस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बिजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले का भी हवाला दिया।

16. अपीलकर्ता/बेलीफ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजय आर. हेगड़े ने वस्तुतः इसी तर्ज पर बहस की। उन्होंने अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता केवल जमानतदार के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और उसने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और उचित और गहन जांच के बाद, पुलिस द्वारा भी ऐसा पाया गया।

17. हम बता दें कि बहस के समय यह पता चला कि जमानतदार के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने श्री हेगड़े को अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र की एक प्रति के साथ-साथ जांच रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। उक्त दस्तावेज़ों को एक नोट के साथ दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है, जब अपीलकर्ता/जमानतकर्ता वारंट निष्पादित करने के लिए उक्त वाद परिसर में गया, तो श्री अक्षय कुमार (शिकायतकर्ता के प्रबंधक) परिसर में मौजूद थे और उन्होंने स्वेच्छा से कब्जा सौंप दिया।

18. दायर किए गए दस्तावेज़ से पता चलता है कि वास्तव में शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्रार, लघु वाद न्यायालय, चेन्नई के समक्ष अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने 26 अप्रैल, 2007 को वारंट के निष्पादन के दौरान गैरकानूनी बेदखली की थी। यह भी शिकायत की गई कि अपीलकर्ता/बेलीफ ने कथित तौर पर उपद्रवी तत्वों का उपयोग करके और घातक हथियारों से लैस होकर, परिसर में घुसकर सभी फर्नीचर तोड़ दिए और सभी मूल्यवान वस्तुओं को हटा दिया। वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए निम्नलिखित दो आरोपों पर VII न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय, चेन्नई द्वारा एक जांच की गई थी:

क) क्या अपराधी कर्तव्य के प्रति लापरवाही का दोषी है?

ख) क्या अपराधी के आरोप साबित हुए हैं या नहीं?

जांच के बाद, VII जज, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, चेन्नई ने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया और माना कि अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ पहला आरोप साबित हो गया है। जहां तक कर्तव्य में लापरवाही के इस आरोप का संबंध है, जांच अधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा

संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 35 के प्रावधानों का उल्लेख किया था। संशोधित प्रावधान, नियम 35 के उप-नियम (4) के रूप में, यह निर्धारित करता है कि जहां किसी घर के कब्जे की डिलीवरी दी जानी है और यह पाया गया कि ताला लगा हुआ है, तो ताला तोड़ने और उसका कब्जा डिक्री होकर को सौंपने के लिए अदालत के आदेश लिए जाएंगे। इस उप-नियम में यह भी कहा गया है कि डिलीवरी के समय यदि घर में कोई चल वस्तु पाई जाती है और निर्णय लेने वाला देनदार अनुपस्थित है, या यदि मौजूद है, तो उसे तुरंत नहीं हटाता है, जिस अधिकारी को डिलीवरी का वारंट सौंपा गया है, वह मौके पर सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में पाए गए सामानों की उनके संभावित मूल्यों के साथ एक सूची बनाएगा, उसे उनके द्वारा सत्यापित कराएं और चल वस्तुओं को डिक्री धारक की अभिरक्षा में छोड़ दें, उसके निपटान के लिए न्यायालय के आदेश लंबित रहने तक वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उससे एक बांड लें। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, जांच अधिकारी ने कब्जे के वारंट के निष्पादन के बाद अपीलकर्ता/बेलीफ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर गौर किया और निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता/बेलिफ ने उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और संपत्ति को केवल डिक्री धारक के एजेंट को सौंप दिया था और इसलिए, वह कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी था।

जहां तक दूसरे आरोप का सवाल है, यह वास्तव में शिकायतकर्ता के आरोप पर आधारित था कि जमानतदार 50-60 उपद्रवी व्यक्तियों के साथ हथियार से लैस होकर आया था और शिकायतकर्ता के परिसर में तोड़फोड़ की थी और सामान फेंक दिया था (यह देखा जा सकता है कि यह आरोप वही है जो एफआईआर का आधार भी है) . हालांकि जांच अधिकारी के मुताबिक जांच में यह आरोप साबित नहीं हुआ. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता कथित घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। जिन दो गवाहों से पूछताछ की गई, उन्होंने बेलिफ़ द्वारा की गई कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित किसी भी तथ्य के बारे में बात नहीं की थी।

19. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि केवल कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप, यानी आदेश XXI नियम 35 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वारंट निष्पादित नहीं करना साबित हुआ है। अपीलकर्ता/बेलीफ ने 19 फरवरी, 2013 को उक्त जांच रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत किया है। अपने स्पष्टीकरण में, बेलीफ ने बताया है कि आदेश XXI नियम 35(4) सीपीसी इस कारण से उपस्थिति पर लागू नहीं होता है, वारंट के निष्पादन के समय परिसर में ताला नहीं लगाया गया था: जांच के दौरान, मृत किरायेदार द्वारा निष्पादन कार्यवाही की चुनौती को इस न्यायालय ने एसएलपी (सी) संख्या 7977-7978/2008 में 07 अप्रैल, 2008 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

20. वर्ष 2013 में जवाब प्रस्तुत करने के बाद आज तक अपीलार्थी के विरूद्ध उसके नियोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

21. शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा दी गई दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दोहराया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, घातक हथियारों से लैस 50-60 उपद्रवी गुंडों और सिविल ड्रेस में एक पुलिस अधिकारी के साथ जमानतदार ने शिकायतकर्ता के परिसर का दौरा किया और उक्त परिसर में तोड़फोड़ की, यहां तक कि शिकायतकर्ता का सामान भी चोरी हो गया। उन्हें इस्पहानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर से बरामद किया गया है, जो अपीलकर्ताओं/जमींदारों से संबंधित था। उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पूरा अपराध अपीलकर्ता और विवादित आदेश के आधार पर आरोपी बनाए गए अन्य व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश/जांच को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। वे उक्त अवैध कृत्यों के अंतिम लाभार्थी थे और उनके द्वारा पर्दे के पीछे से इन अवैध कृत्यों को प्रायोजित और साजिश रचे बिना, यह घटना घटित नहीं होती। शिकायतकर्ता के परिसर से चुराए गए सामान को अपीलकर्ता द्वारा संचालित एलस्पाहानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर में ले जाया गया था और जांच के दौरान उक्त परिसर से उसे बरामद किया गया था और उक्त तथ्य

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में परिलक्षित हुए हैं। , जिसमें PW1 भी शामिल है, यानी यहां शिकायतकर्ता, जिसने कथित घटना में अपीलकर्ता और अपीलीय आदेश के आधार पर शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से गवाही दी है।

22. विद्वान वकील ने आगे पीडब्लू-4 के बयान का हवाला दिया, जिसने प्रश्न में अपराध की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया है। उन्होंने अपनी गवाही में कहा है, "...उन्होंने धैर्य खो दिया और 20 लोगों ने कार्यालय से सारा सामान फेंक दिया।" उन्होंने इमारत के सामने वाले हिस्से में लॉरी में सामान फेंक दिया, इस वचन के साथ कि वे सभी सामान हमारे एमडी निवास श्री योगेन्द्र चांडक को भेज देंगे, बाद में लॉरी में ले जाया गया उक्त सामान मेरे एमडी निवास में नहीं पहुंचा। मुझे उस कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जिसमें परिसर का ख़ाली कब्ज़ा सौंप दिया गया था, हालाँकि वहाँ कुछ और लेख भी थे। उन्होंने धमकी दी और मेरे हस्ताक्षर पर लोगों के एक समूह द्वारा हमला किया गया..." "...इसके बाद मुझे पता चला कि उक्त लोग पुलिस अधिकारी नहीं हैं। वो लोग इमारत के मकान मालिकों द्वारा भेजे गए थे..."

23. उपरोक्त आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में PW1 से PW6 की गवाही में यह बताने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर आई है कि अपराध के अपराधी केवल अपीलकर्ता के कर्मचारी नहीं थे लेकिन जैसा कि अपीलकर्ता ने स्वयं कहा था और उनके कहने पर यह कार्रवाई हुई और इतना ही नहीं आपराधिक धमकी और जगह में तोड़फोड़ करने के बाद, सामान चोरी कर लिया गया और/या अपीलकर्ता के परिसर में ले जाया गया। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करना चाहिए, वकील की दलील थी।

24. विरोध याचिका दायर न करने पर आधारित तर्क का जवाब देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया: (ए) गवाही की रिकॉर्डिंग के दौरान अपीलकर्ता को फंसाने वाले ताजा सबूत आए हैं; (बी) तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के नाम को

छोड़कर आरोप पत्र दायर किया गया था, शिकायतकर्ता के ध्यान में नहीं लाया गया था। यहां तक कि ट्रायल कोर्ट भी इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य मामले में इस कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए ऐसे तथ्य के संबंध में शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी करने में विफल रहा। उन्होंने गीता राम बनाम वेदी राम और अन्य के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि धारा 319 सीआरपीसी के प्रावधानों को तब भी लागू किया जा सकता है, जहां तलब किए गए व्यक्ति का नाम एफआईआर में है, फिर भी उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। और उसके बाद कोई विरोध याचिका दायर नहीं की गई।

25. उन्होंने सुमन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 5 तथा हरदीप सिंह मामले में इस न्यायालय के निर्णयों की भी सहायता ली।

26. इस प्रकार, उन्होंने निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के निष्कर्ष कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हैं और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

27. जहां तक सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय की उन व्यक्तियों को भी सम्मन करने की शक्ति है जिनका आरोप पत्र में नाम नहीं है, पेश होने और मुकदमे का सामना करने के लिए, यह निर्विवाद है। सीआरपीसी की धारा 319 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करना है, जिन्हें आरोपपत्र दाखिल होने के समय फंसाया नहीं गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान अदालत को पता चला कि उन्हें बुलाने और मुकदमे का सामना करने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर आ गए हैं। हरदीप सिंह के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस संबंध में कानून को आधिकारिक घोषणा के साथ सुलझा लिया है, जिससे पहले इस प्रावधान की व्याख्या करते समय जो जाल बनाया गया था, वह दूर हो गया है। जहां तक सीआरपीसी की धारा 319 के पीछे के उद्देश्य का सवाल है, न्यायालय ने इस पर प्रकाश डाला था:

"अदालत न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने का कर्तव्य उस पर डाला गया है, इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों के पास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को नकारना अनुचित होगा जहां यह असामान्य नहीं है कि वास्तविक आरोपी, कभी-कभी जांच और/या अभियोजन एजेंसी में हेरफेर करके बच जाते हैं। मुकदमे से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि एक आरोपी कभी-कभी जांच या पूछताछ के चरण में भी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध के कमीशन से जुड़ा हो।"

28. कुछ समय में, संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल न्यायालय में दर्ज 'साक्ष्य' पर किया जा सकता है, न कि जांच चरण में एकत्र की गई सामग्री पर, जिसका सीआरपीसी की धारा 190 के तहत स्तर पर परीक्षण किया जा चुका है। और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करना। हरदीप सिंह के मामले में निर्धारित इस सिद्धांत को बिजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में निम्नलिखित तरीके से समझाया गया है:

"10. यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 319, जो एक सक्षम प्रावधान है जो न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार देता है, चाहे वह आरोपी न हो, आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है और फैसले की घोषणा से पहले, सीआरपीसी की धारा 207/208, कमिटमेंट आदि के चरण को छोड़कर, जो केवल एक पूर्व-परीक्षण चरण है जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को गति देना है।

11. हरदीप सिंह मामले में संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर भी विवाद सुलझा लिया है कि क्या सीआरपीसी की धारा 319(1) में इस्तेमाल किया गया शब्द "साक्ष्य"

व्यापक अर्थ में इस्तेमाल किया गया है और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को इंगित करता है या शब्द "साक्ष्य" परीक्षण के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक ही सीमित है। यह माना जाता है कि यह वह सामग्री है, जो न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद, किसी अपराध की जांच या कोशिश करते समय उसके पास उपलब्ध होती है, जिसे अदालत अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए सहायक कारणों के लिए उपयोग कर सकती है या विचार कर सकती है। "सबूत" शब्द को परीक्षण के स्तर पर और यहां तक कि जांच के स्तर पर भी इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को बुलाने के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग उसके सामने लाई गई किसी भी सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। साथ ही, इस न्यायालय ने आगाह किया कि मुकदमे के दौरान सबूत दिए जाने के बाद ऐसी सामग्री पर सचेत रूप से ऐसी शक्तियों को लागू करना अदालत का कर्तव्य और दायित्व अधिक कठिन हो जाता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत "साक्ष्य" की मुख्य जांच भी की जा सकती है और न्यायालय को तब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऐसे साक्ष्य का जिरह पर परीक्षण न हो जाए क्योंकि यह अदालत की संतुष्टि है जिसे अपराध में मुकदमे का सामना नहीं कर रहे किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) की मिलीभगत के संबंध में अदालत द्वारा दर्ज किए गए कारणों से एकत्र किया जा सकता है।

12. हालाँकि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए संतुष्टि की डिग्री आवश्यक है और संबंधित प्रश्न यह है कि किस स्थिति में इस शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति के संबंध में किया जाना चाहिए जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन आरोप पत्र दायर नहीं किया

गया है। इन दो पहलुओं को हरदीप सिंह मामले में संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से निपटाया गया था और निम्नलिखित तरीके से उत्तर दिया गया था: (एससीसी पीपी. 135 और 138. पैरा 95 और 105-106)

"95. संज्ञान लेने के समय, अदालत को यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत, हालांकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, संतुष्टि की जिस मात्रा की आवश्यकता है वह बहुत सख्त है। विकास बनाम राजस्थान राज्य [विकास बनाम राजस्थान राज्य, (2014) 3 एससीसी 321: (2014) 2 एससीसी (सीआरआई) 172] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि [सं.: दो तारों के बीच के शब्दों पर मूल रूप से जोर दिया गया है।] वस्तुनिष्ठ संतुष्टि [एड.: दो तारों के बीच के शब्दों पर मूल रूप से जोर दिया गया है।] अदालत में किसी व्यक्ति को "गिरफ्तार" या "सम्मन" किया जा सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, यदि साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

***

105. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से मजबूत और

ठोस सबूत मिलते हैं, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के समक्ष जेड के साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए, इसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय किया गया था, लेकिन सबूतों से एक हद तक संतुष्टि कम है। यदि अप्रतिवादित हो जाता है। दृढ़ विश्वास की ओर ले जाएगा. ऐसी संतुष्टि के अभाव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 319 में यह प्रदान करने का उद्देश्य कि क्या "साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है" शब्दों से स्पष्ट है " [संपादित करें: दो तारों के बीच के शब्दों पर मूल रूप से जोर दिया गया है।] जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है [एड.: दो तारांकन चिह्नों के बीच के शब्दों पर मूल रूप से जोर दिया गया है।]"। इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके"। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है:"

(जोर दिया गया)

13. प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हरदीप सिंह मामले में प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों को दोहराया जा सकता है: धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान किसी भी चरण में किया जा सकता है, यानी मुकदमे के समापन

से पहले, किसी भी व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाना और चल रहे मामले में मुकदमे का सामना करना, जब ट्रायल कोर्ट को पता चले कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ "'सबूत" हैं जिनके आधार पर यह इकट्ठा किया जा सकता है कि वह अपराध का दोषी प्रतीत होता है। यहां "'साक्ष्य" का अर्थ उस सामग्री से है जो मुकदमे के दौरान अदालत के सामने लाई जाती है। जहां तक जांच के चरण में आईओ द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य का सवाल है, इसका उपयोग पुष्टि के लिए और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। निःसंदेह, ऐसे साक्ष्य जो गवाहों से जिरह किए बिना मुख्य परीक्षण में सामने आए हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है। हालाँकि, चूँकि यह सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत को दी गई एक विवेकाधीन शक्ति है और एक असाधारण शक्ति भी है, इसका प्रयोग केवल उन मामलों में संयमित रूप से किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियाँ उचित हों। संतुष्टि की डिग्री उस डिग्री से अधिक है जो दूसरों के खिलाफ आरोप तय करने के समय आवश्यक होती है जिनके संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से मजबूत और ठोस सबूत मिले। इसका अभ्यास आकस्मिक या अभद्र तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया जो राय बनाई जानी है, उसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता है।"

29. सीआरपीसी की धारा 319 के उपरोक्त दायरे को ध्यान में रखते हुए, अब हम वर्तमान मामले की जांच के लिए आगे बढ़ते हैं।

30. विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश से पता चलता है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता के आवेदन को खारिज करते समय, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दो विचारों से प्रभावित थे:

(ए) शिकायतकर्ता (पीडब्लू-।) ने अपने मुख्य परीक्षण में अपीलकर्ताओं, यानी मकान मालिकों और जमानतदार के बीच हुई कथित साजिश के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। इसके अलावा अन्य गवाहों, यानी पीडब्ल्यू 2, 3 और 4, जो वास्तव में शिकायतकर्ता की कंपनी में काम कर रहे थे, ने अपीलकर्ताओं के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था। शिकायतकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, उपलब्ध 'साक्ष्य' अपीलकर्ताओं/प्रस्तावित आरोपियों को मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था।

(बी) पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था जिसमें अपीलकर्ताओं को फंसाया नहीं गया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने उस स्तर पर कभी कोई विरोध याचिका दायर नहीं की।

31. उपरोक्त आधारों को अपने तर्क के रूप में लेते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में कोई 'सबूत' नहीं है। तर्क यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर किया गया आवेदन शिकायतकर्ता की ओर से बाद में सोचा गया और देर से किया गया प्रयास था, जो पीडब्लू-1 के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के बहुत बाद दायर किया गया था, वह भी तब जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पहले ही समाप्त हो चुके थे।

32. उपरोक्त के विपरीत, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में, इस तथ्य से प्रभावित किया है कि अपीलकर्ताओं के नाम एफआईआर में और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान में भी उल्लेखित थे। इन अपीलकर्ताओं को नामित किया गया था और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत ऐसे बयान 'दस्तावेज' बनेंगे। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने देखा है कि सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में 'सबूत' में उपरोक्त बयान शामिल होंगे और इसलिए, अपीलकर्ताओं को बुलाया जा सकता है।

33. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त कारण न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरते। उच्च न्यायालय ने विषय वस्तु को ठीक से नहीं निपटाया है और अपीलकर्ता के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूतों के अभाव में भी, उसने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है और अपीलकर्ताओं को आरोपी व्यक्तियों के रूप में बुलाने में अपने विवेक का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक स्थान पर संविधान पीठ ने लारदीप सिंह के मामले में कहा था कि 'साक्ष्य' शब्द को इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए, मुकदमे के चरण में भी और पूछताछ के चरण में भी। हालाँकि, फैसले के पैराग्राफ । 05 में, यह देखा गया है कि 'केवल जहां अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत मिलते हैं, वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से। इस वाक्य से यह आभास होता है कि केवल वही साक्ष्य देखा जाना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, न कि वह साक्ष्य जो जांच के चरण में एकत्र किया गया था। हालाँकि दोनों टिप्पणियों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 'सबूत', किसी चल रहे मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए किसी अभियुक्त को जिस आधार पर बुलाया जाना है, वह वह सामग्री होनी चाहिए जो मुकदमे के दौरान अदालत के सामने लाई जाए। जांच के चरण में जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य का उपयोग केवल पुष्टि के लिए और सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

34. इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज किया जाता है, लेकिन पुलिस जांच के बाद उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे फंसाए बिना आरोप पत्र दायर करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है, और सम्मन के चरण में, यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी के रूप में बुलाया जाना चाहिए, भले ही

आरोप पत्र में उसका नाम न हो, तो वह ऐसा कर सकता है। उस स्तर पर, शिकायतकर्ता को भी एक विरोध याचिका दायर करने का मौका दिया जाता है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों को भी बुलाने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम एफआईआर में था लेकिन आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था। एक बार वह चरण बीत जाने के बाद, सीआरपीसी की धारा 319 के आधार पर न्यायालय अभी भी सशक्त नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब लागू होती है जब मुकदमे के दौरान प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।

35. उपरोक्त के मद्देनजर, स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों पर भरोसा करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था। यह केवल पुष्टिकारक सामग्री हो सकती है। पहले उदाहरण में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 'साक्ष्य' पर विचार किया जाना था। जहां तक अदालत में दिए गए पीडब्लू-। के बयान का सवाल है, उक्त बयान को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपीलकर्ताओं/जमींदारों की ओर से किसी साजिश का आरोप नहीं लगाया है। दरअसल, किसी भी गवाह ने ऐसा नहीं कहा है. इसके अभाव में, इस महत्वपूर्ण तथ्य के साथ कि कथित घटना होने पर ये अपीलकर्ता/मकान मालिक कथित तौर पर साइट पर मौजूद नहीं थे, हमें सीआरपीसी की धारा 319 के अर्थ में कोई 'सबूत' नहीं मिलता है। जिसके आधार पर उन्हें आरोपी व्यक्ति के रूप में तलब किया जा सके। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 ने घटनास्थल पर हुई घटना और वहां मौजूद व्यक्तियों के कथित व्यवहार के तरीके के बारे में गवाही दी है। पीडब्लू-4 के बयान में उन्होंने आरोप लगाया है कि "बाद में मुझे पता चला कि उक्त लोग पुलिस अधिकारी नहीं हैं, लोगों को इमारत के मकान मालिकों ने भेजा था..."। वह बयान आईपीसी के उन प्रावधानों के तहत आरोप का सामना करने के लिए अपीलकर्ताओं/जमींदारों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है जिनके तहत अन्य पर आरोप लगाए गए हैं। हरदीप सिंह के मामले में उल्लिखित साक्ष्यों के मानक, अर्थात् 'मजबूत और ठोस साक्ष्य' का अभाव है।

36. जहां तक अपीलकर्ता/जमानतदार का सवाल है, एफआईआर या अदालत में पीडब्लू 1 से 6 के बयान में कोई विशेष आरोप नहीं है। जहां तक विभागीय जांच का सवाल है, जो बेलीफ के खिलाफ की गई थी, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, उसे केवल कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, अन्य आरोप का नहीं। प्रासंगिक रूप से, उक्त जांच में, सोचा गया कि वास्तविक शिकायतकर्ता उपस्थित हुआ और उसने एक अन्य गवाह भी पेश किया, इन आरोपों पर अपीलकर्ता/बेलीफ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके कारण जांच अधिकारी ने भी माना कि ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ है . इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक निर्धारक कारक नहीं है क्योंकि आपराधिक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, प्रकृति में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालाँकि, प्रासंगिक बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान पुलिस को अपीलकर्ता/बेलिफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और यहां तक कि विभाग को भी विभागीय जांच में उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ता/बेलिफ के खिलाफ कोई 'मजबूत और ठोस सबूत' सामने नहीं आया है जिसके आधार पर उसे बुलाया जा सके।

37. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रायल कोर्ट आरोप पत्र में शामिल व्यक्तियों को बुलाने के समय शिकायतकर्ता को कोई नोटिस जारी करने में विफल रहा। हालाँकि, जहाँ तक ट्रायल कोर्ट के प्रारंभिक सम्मन के मुद्दे का सवाल है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को सम्मन नहीं किया गया था, इस आदेश को शिकायतकर्ता द्वारा मंच पर चुनौती नहीं दी गई थी। इस स्तर पर, हम केवल सीआरपीसी की धारा 319 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग से चिंतित हैं। जहां तक गीता राम के मामले में फैसले का सवाल है, इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि धारा 319 के प्रावधानों को तब भी लागू किया जा सकता है, जहां व्यक्ति का नाम एफआईआर में है, फिर भी उसके

खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि सवाल यह है कि क्या मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का उचित प्रयोग किया गया है।

38. तदनुसार, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देते हैं और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल करते हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल अपील की अनुमति.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।